जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 14 संख्याः 277 प्रभात हिण्डौन सिटी, रविवार 7 अगस्त, 2022 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

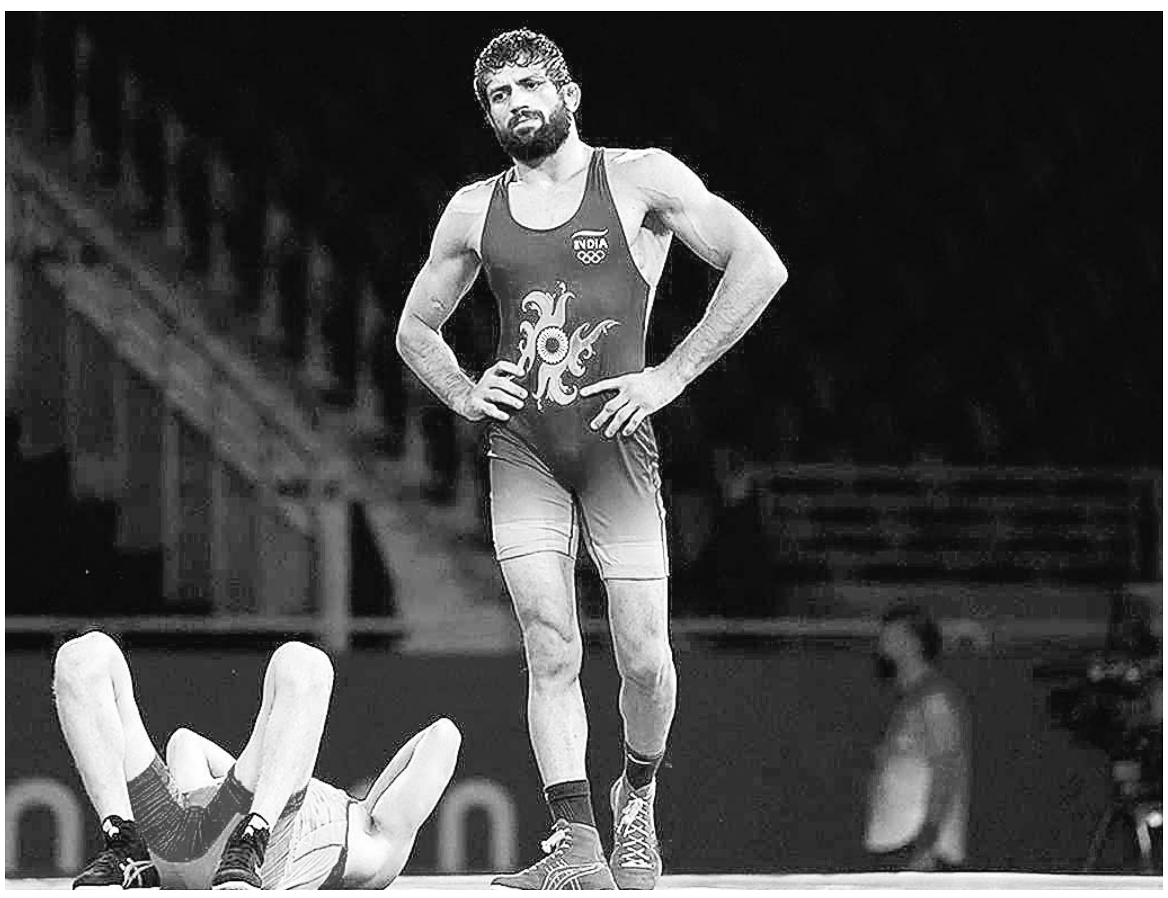

टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मैडलिस्ट रवि दहिया ने कॉमनवैल्थ गेम्स में भी भारत का गौरव बढ़ाया है। रवि दहिया ने कुश्ती के पुरुष 57 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। रवि ने 57 किग्रा फाइनल में नाइजीरिया के वेल्सन एबीकेवेनिमो को तकनीकी श्रेष्ठता से हराकर स्वर्ण पदक जीता। कॉमनवैल्थ गेम्स में तीन बार के पदक विजेता वेल्सन मुकाबले की शुरुआत में रवि को पॉइंट स्कोर करने का कोई मौका नहीं दे रहे थे, लेकिन रवि ने अंततः उनके पैरों को जकड़कर पॉइन्ट्स की झड़ी लगा दी और कॉमनवैल्थ गेम्स में अपना पहला स्वर्ण हासिल किया। इसके अलावा पहलवान पूजा गहलोत ने 50 किग्रा के कांस्य पदक के लिए खेले गये मैच में स्कॉटलैण्ड की क्रिस्टेल लेमोफेक को मात दी।

जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित

धनखड़ को 528 वोट मिले, इतने वोट तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कृष्ण कांत, भैरोंसिंह शेखावत, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू को भी नहीं मिले थे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अगस्त। भारत ने अपना नया उपराष्ट्रपति चुन लिया है। वह है राजस्थान के झुंझुनूं के मूल निवासी जगदीप धनखड़।

जगदीप धनखड़ को एन.डी.ए. प्रत्याशी के रूप में 528 वोट मिले, जबकि विपक्ष की मारग्रेट अल्वा के खाते में 182 वोट गए।

इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वोटिंग में भाग ना लेने का निर्णय था। यह आश्चर्यजनक था क्योंकि जब धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब वह ममता के सभी कार्यों राजनीतिक निर्णयों में हस्तक्षेप किया करते थे और मुख्यमंत्री ने उनसे पीछा छुड़ाने के भरसक प्रयास किये थे।

और अन्ततः जब उन्हें वहां से हटाकर उपराष्ट्रपति पद के लिए मोदी की पसंद के रूप में चयनित किया गया, तब भी ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) ने उनके खिलाफ वोट नहीं किया। वास्तव में उनकी पार्टी ने एक भी वोट नहीं डाला। इससे इन अटकलों को बल मिला है कि उन्होंने मोदी के साथ कोई सौदेबाजी कर ली है। ममता के 34 सांसदों ने वोट नहीं डाला।

- उपराष्ट्रपति चुनाव का एक रहस्यमय पहलू रहा ममता बनर्जी की भूमिका। हालांकि, उन्होंने धनखड़ को प. बंगाल के राज्यपाल के पद से हटाने के लिए ऐड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया, राज्यपाल के रूप में धनखड़ की भूमिका से तंग होकर, पर अंत में धनखड़ का जाना तय हो गया तो उन्होंने धनखड़ के खिलाफ वोट नहीं किये।
- उनके इस निर्णय को प्र.मंत्री मोदी के नज़दीक जाने का संकेत माना गया।
- धनखड़ की राजनीतिक यात्रा काफी रोचक रही है। पहले वे जनता दल में थे, फिर कांग्रेस से जुड़े और अन्ततोगत्वा भाजपा से नाता जोड़ा व प. बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए।

धनखड़ राजस्थान विधानसभा में विधायक रहे और फिर केन्द्र की चन्द्रशेखर सरकार में मंत्री रहे। वह एक बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं।

राज्यसभा में उनका प्रवेश पहली बार होगा क्योंकि वह कभी इसके सदस्य नहीं रहे।

चुनाव के पीठासीन अधिकारी उत्पल सिंह द्वारा उनकी जीत की घोषणा कर उन्हें सर्टिफिकेट देने के बाद उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उनसे भेंट कर उन्हें जीत की बधाई देंगे।

अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संचालन प्रमुख राजस्थान से हैं,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्रीय सरकार व तमिलनाडू लेई-देई में फंसे जी.एस.टी. के मसले पर

निर्मला सीतारमन ने भाजपा की केन्द्रीय सरकार की ओर से मोर्चा संभाला, तमिलनाडू के वित्त मंत्री पी.टी.आर. ने पलट वार किये

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अगस्त। अर्थशास्त्र या कहें कि अर्थव्यवस्था की सार-सँभाल तथा इश्यू वेलफेयर अर्थशास्त्र तमिलनाडु को केन्द्र के साथ सीधे टकराव की स्थिति में ले आया है।

संसद में महँगाई पर हुई बहस के दौरान, डी.एम.के. सदस्य कनिमोई की ओर से की गई आम आदमी के उपयोग में आने वाली जरूरी चीजों पर जी.एस.टी. लगाये जाने की आलोचना तथा तमिलनाडु के वित्त मंत्री द्वारा दिये गये पेट्रोलियम उत्पादों पर सैन्ट्रल एक्साइज में कटौती के सुझाव के दंशों से पीड़ित केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिल भाषा में जवाब दिया, उन्होने इसे राज्य का पाखंड बताया क्योंकि वह जी.एस.टी. पर हुए निर्णयों में शामिल है पर बाहर आकर इसकी आलोचना कर रहा है। केन्द्र द्वारा की गई एक्साइज कटौती की याद दिलाते हुए, सीतारमण ने पूछा कि आम आदमी को राहत देने के लिये तमिलनाडु वी.ए.टी. (वैट) में कमी क्यों नहीं कर सका। उन्होंने चुनावी वादों को पूरा नहीं करने के लिये तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी की कटु आलोचना की। उसके बाद, तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ हमलों की भी शुरुआत कर दी।

भाजपा नेताओं का कहना है कि जहाँ केन्द्र ने पेट्रोल तथा डीज़ल की एक्साइज ड्यूटी में क्रमशः 14.50 रू. तथा 17 रू. की बड़ी कटौती कर दी है, वहीं राज्य सरकार ने वैट में मात्र 3 प्रतिशत कटौती की है तथा केन्द्र को जन-कल्याण पर भाषण दे रही है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- निर्मला सीतारमन ने पहला वार किया, यह कह कर कि, तमिलनाडू, जी.एस.टी. की बैठक में तो सभी प्रस्तावों पर सहमति जताता है, पर बैठक से बाहर आकर उन निर्णयों की कड़ी आलोचना करता है।
- तमिलनाडू के वित्त मंत्री पी.टी.आर. ने प्रत्युत्तर में कहा कि, जिस तरह का ''वोटिंग सिस्टम'' है जी.एस.टी. काउन्सिल में, उसमें 30 प्रतिशत वोटिंग राइट्स केन्द्रीय सरकार के पास रहते हैं, बाकी सभी राज्यों में बांटे जाते हैं, राज्य सरकार की आवाज में कुछ दम नहीं होता।
- पी.टी.आर. ने यह भी कहा कि, निर्मला सीतारमन, तमिलनाडू पर ताना मारती हैं कि, राज्य सरकार पैट्रोल व पैट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स घटाने को तैयार नहीं, आम आदमी को रिलीफ देने के लिये। पर, वे (निर्मला सीतारमन) भूल जाती हैं कि, केन्द्रीय सरकार ने गत सात साल से पैट्रोल, डीज़ल पर टैक्स में कई बार बढ़ोतरी की है, जबकि तमिलनाडू सरकार ने एक बार भी टैक्स नहीं बढ़ाया।
- पी.टी.आर. ने यह भी कहा कि, जब से जी.एस.टी. व्यवस्था लागू हुई है, राज्य सरकारों के पास आमदनी का कोई और स्रोत नहीं रह गया है, अतः वे पैट्रोल पर टैक्स कम करके, अपने आर्थिक साधन कितना घटा दें।

रिलायंस बनाम सेबी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अगस्त। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने एक फैसले में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (एस.ई.बी.आई.) ऑफ इंडिया की खिंचाई की क्योंकि उसने न्यायमूर्ति (सेनि) बी.एन. श्रीकृष्ण की राय के कुछ अंशों की ''चैरी-पिंकिंग की थी, जबकि उस सूचना को प्रकट करने के लिये इनकार कर दिया गया था, जो रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) को दोष मुक्त किये जाने से सम्बन्धित थी।

यह केस उस याचिका से सम्बन्धित है, जो सुप्रसिद्ध चार्टर्ड अकान्टेंट एस.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2002 में एस. गुरूमूर्ति की शिकायत पर दर्ज केस में रिलायंस के पक्ष में फैसला सुनाया और सेबी को कड़ी फटकार लगाई व कहा कि, रिलायंस को जस्टिस बी.एन. कृष्णा की राय के सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाए।

पूर्व मु.मंत्री पलानीस्वामी ने डी. एम. के. की पूर्ण बागडोर संभाली

पर पलानीस्वामी व पनीरसेल्वम की, पार्टी पर एकाधिकार की लड़ाई ने भाजपा का रास्ता साफ किया, तमिलनाडू में प्रवेश करने का

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अगस्त। तमिलनाडू की मुख्य विपक्षी पार्टी ए.आई.ए.डी.एम.के. अर्थात अन्नाद्रमुक जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री एडापड्डी पलानिस्वामी ने कब्जा कर लिया है, की आपसी लड़ाई ने सत्तारूढ़ डी.एम.के. को एक तरह से खुली छूट दे दी है।

विपक्षी ए.आई.ए.डी.एम.के. के सबसे बड़े दो नेताओं एवं पूर्व मुख्यमंत्रियों पलानिस्वामी और ओ. पनीर सेल्वम (ओ.पी.एस.) के बीच एक-दूसरे को खत्म करने की लड़ाई का खात्मा पलानिस्वामी के पार्टी पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने और अपने शत्रु को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटाने के साथ हुआ।

पार्टी से निष्कासन होने के बाद ओ.पी.एस. पार्टी का पूर्ण नियंत्रण पलानिस्वामी को सौंपने वाली पार्टी की कार्यवाहियों को रद्द करवाने के लिए एक के बाद एक कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे हैं। उनका अंतिम विधिक कदम गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेना था, जिसमें उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के उस निर्णय को पलटने की मांग की जिसके तहत ए.आई.ए.डी.एम.के. मुख्यालय का स्वामित्व पलानिस्वामी को दे दिया गया था। वास्तव में मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक अलग आदेश में ए.आई.ए.डी.एम.के. की जनरल काउन्सिल की एक मीटिंग करने की भी अनुमति प्रदान की थी जिसमें ओ.पी.एस. को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अन्ततः निष्कासित कर दिया गया और ई.पी.एस. को ए.आई.ए.डी.एम.के. अंतरिम महासचिव चुन कर उन्हें पार्टी का पूर्ण नियंत्रण सौंप दिया गया था।

पार्टी के समन्वयक एवं अपने विरोधी ओ.पी.एस. को पार्टी से बाहर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भाजपा के इस प्रयास को मजबूती मिल रही है, नये प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलाई की सक्रियता से।
- अन्नामलाई, कर्नाटक कैडर के आई.पी.एस. अफसर हैं तथा तमिलनाडू में आम जनता को छूने वाले मामलों को पुरज़ोर ढंग से उठा रहे हैं।
- केन्द्र में भी भाजपा की ही सरकार है, इससे अन्नामलाई का काम कुछ आसान हो जाता है, छोटी-छोटी पार्टियों का डी.एम.डी.के. से गठबंधन कराने में।
- जैसा कि विदित ही है, गत लोकसभा चुनाव में तमिलनाडू की 39 सीटों में से एक को छोड़कर सभी सीटों पर डी.एम.के. ने जीत हासिल की थी। अब अगर भाजपा छोटी-छोटी पार्टियों से गठबंधन कर, एक सशक्त विकल्प प्रस्तुत करती है डी.एम.के. का, तो वाकई में अन्नामलाई की भारी सफलता मानी जायेगी।

पानी निकासी

सुजानगढ़ , 6 अगस्त (निसं)। गैनाणी से ताल की ओर पानी निकासी के लिए डाली गई पाईप लाईन के बार-बार लीकेज की समस्या को दूर करने के लिए नगरपरिषद द्वारा शीघ्र ही नई पाईप लाईन डाली जायेगी। नगरपरिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि गैनाणी से ताल में पानी छोड़ने के लिए 45 साल पहले, वर्ष1977 में पाईप लाईन डाली गई थी, जो बार बार लीक हो रही थी, और इससे कभी भी भारी समस्या आ सकती थी। प्रशासन आपदा के तहत 70 से 75 लाख रु. तक एस्टीमेट बनाकर टेंडर निकाल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- 45 साल पहले पानी निकासी के लिए डाली गई पाइप लाईन के ऊपर बना लिए मकान, लीकेज से आया घरों में पानी, अब 75 लाख रूपये की लागत से नगर परिषद डालेगी नई पाईप लाईन।

प्र.मंत्री व गृह मंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं, वरूण गांधी की ''अठखेलियों'' पर ध्यान न दें?

हाई कमान का शायद मानना है कि, वरूण गांधी के खिलाफ कार्यवाही करने से बेवजह मेनका गांधी के भाजपा में प्रवेश व मंत्री के रूप में भूमिका चर्चा का विषय बनेगी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अगस्त। अक्खड़ स्वभाव के भाजपा नेता वरूण गांधी, जो तीन बार लोकसभा सांसद रहे हैं, द्वारा अपनी पार्टी, सरकार तथा नेतृत्व के खिलाफ किए गए कटाक्षों तथा अनेक बार की गई कटु निन्दा के बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा किसी प्रकार के उकसावे में नहीं आ रही हैं। उनका नवीनतम निशाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं जिनके विपक्ष पर किए गए ''रेवड़ी'' कटाक्ष पर वरूण ने तीखी टिप्पणी की जो चर्चा का विषय बन गई है।

पीलीभीत सांसद वरूण गांधी ने अपनी सरकार पर तीखा व्यंग्य उस समय किया, जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कहा कि जनता को मुफ्त राशन देने के लिये सरकार को बधाई दी जानी चाहिये। पिछले पाँच सालों में डूबत ऋण की बहुत बड़ी राशि, जिसे ''राइट ऑफ'' (माफ) कर दिया, की तुलना मुफ्त राशन देने से करते हुये, वरूण ने हिन्दी में ट्वीट किया, ''जो सदन गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त देने के लिये ''धन्यवाद'' की अपेक्षा करता है, वही सदन यह भी बताता है कि पिछले पाँच सालो में 10 लाख करोड़ रू ऋण को माफ कर दिया गया है।

वरूण आगे कहते हैं, ''मुफ्त रेवड़ी'' वाली सूची में सबसे ऊपर मेहुल चोकसी तथा ऋषि अग्रवाल के नाम है। सरकारी फंड पर पहला अधिकार किसका है?''

उनकी इस पोस्ट के साथ ही, वित्तराज्य मन्त्री भागवत के. कराड़ द्वारा संसद में पेशस किये गये आँकड़े भी दिये हुये हैं।

निशिकान्त दुबे ने अभी हाल ही में लोकसभा में कहा था कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिये मोदी सरकार को बधाई दी ही जानी चाहिये।

प्रधानमंत्री ने पिछले माह उस समय एक उपद्रव खड़ा कर दिया था, जब उन्होंने ''रेवड़ी कल्चर'' के खिलाफ जनता को चेतावनी दी थी।

उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के बाद, जन समुदाय को सम्बोधित करते हुये, मोदी ने कहा था, कि मुफ्त चीजें देने के वादों पर वोट माँगने की राजनैतिक दलों की प्रवृत्ति देश के लिये खतरनाक हो सकती हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पर, भाजपा हाई कमान के इस अभय दान का भरपूर ''लाभ'' उठा रहे हैं वरूण गांधी।
- उन्होंने नवीनतम खिल्ली, प्र.मंत्री मोदी के राजनीतिक दलों की ''रेवड़ी सभ्यता'' के खिलाफ दिये गये भाषण की उड़ाई।
- वरूण गांधी ने भाजपा सांसद निशीकांत दुबे द्वारा संसद में दिये भाषण को लक्ष्य बनाकर कहा, ''वे (निशीकांत दुबे) चाहते हैं, भारत की जनता प्र.मंत्री का आभार माने कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री बंटवाया।
- वरूण ने कहा कि, इसी दौरान केन्द्रीय सरकार ने 10 लाख करोड़ रूपये के ऋण माफ किये, मित्र उद्योगपतियों के।

धमोरा गांव का लाडला

गुढ़ागौड़जी, 6 अगस्त (निसं)। कस्बे के निकटवर्ती गांव धमोरा की जाखड़ों की ढाणी का दुष्यंत सिंह जाखड़ थाईलैंड के नाखोन-पथोम शहर में वॉलीबाल आयोजित होने वाले सात दिवसीय ए.वी.सी. कप में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व करेगा। भारत की19 सदस्यीय टीम शुक्रवार को कोलकाता के नेताजी सुभाषचंद्र बोस एयरपोर्ट से थाइलैंड के लिए रवाना हुई।

भारतीय वॉलीबाल महासंघ के सचिव अनिल चौधरी ने ए.वी.सी. कप में भाग लेने वाली भारतीय टीम की घोषणा की थी। यह टीम थाइलैंड में दुष्यंतसिंह जाखड़ की कप्तानी में चैम्पियन बनने के लिए दमखम दिखाएगी। दुष्यंत का परिवार भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- धमोरा गांव के दुष्यंत सिंह जाखड़ थाईलैंड में हो रही ए.वी.सी. कप वॉलीबॉल में भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए हैं।